so far been taken to implement the recommendations of the Man Singh Committee Report?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : A number of committees have gone into this problem as to how the flood situation in the Damodar area could be handled, and the problem is very complicated and varied. The natural flood plains through which the drainage should take place have been encroached upon; a lot of unauthorised encroachments have taken place there and the State Government is not able to control these constructions with the result it has not been possible to avert the problem. Now, flood. irrigation, these are State subjects and, as I said, if the Government of West Bengal has any proposal for construction of dams or controlling flood in the Damodar area we would certainly consider it. A scheme costing about Rs. 14 crores is being examined in that respect and we would see that it is implemented at the earliest.

सूखे का योजना पर प्रभाव

*83. **श्री मीर्जा इर्शादबेग :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भयंकर अकाल का देश की वित्तीय स्थिति और पंचवर्षीय योजना विशेषत: कृषि तथा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ख) देश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं; और

(ग) क्या इस भयंकर सूखे के कारण हमारे लक्ष्यों की पूर्ति मे बाधा उत्पन्न होने की संभावना है और यदि हां, तो कहां तक ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्य-क्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) से (ग) इस वर्ष पूरे देश में व्याप्त सूखे ने देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है । कृषि क्षेत्र में, प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, खरीफ उत्पादन पिछले वर्ष के 86 मिलियन टन के मुकाबले लगभग 70 से 73 मिलियन टन होगा । रबी के मौसम मे अधिक उत्पादन के जरिए इस क्षति को पूरा करने के लिए यथासम्भव उपाय किए जा रहे है । फिर भी वर्ष 1986-87 के मुकाबले वर्ष 1987-88 में कुल कृषि उत्पादन कम होगा । तथापि वर्तमान संकेतों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि सूखे का औद्योगिक उत्पादन पर बहुत गम्भीर प्रभाव नही पड़ेगा ।

योजना आयोग का प्रारंभिक अनुमान यह है कि गम्भीर सूखे के बावजूद अर्थव्यवस्था मे कुल मिलाकर संवृद्धि होगी । यह संकेत है कि सातवी योजना के लक्ष्य सूखे से बहुत अधिक प्रभावित नही होगे ।

प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने के लिए राहत कार्यों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया गया है । 1987-88 में मानसून के बाद सूखा-राहत के लिए मन्जूर किए गए व्यय की सीमा पहले ही 702 करोड़ रु निर्धारित की जा चुकी है । अधिक व्यय की तभी मन्जूरी दी जाएगी जब गुजरात (सितम्बर, 87-मार्च, 1988) और राजस्थान (अक्तूबर, 1987-मार्च, 1988) के लिए केन्द्रीय दलों की सिफारिशो पर विचार कर लिया जाएगा । इसके अलावा सूखा रोकने के प्रबंधों के भाग के रूप मे निर्धारित सिचाई कार्यों के लिए 118 करोड़ रु० की और व्यवस्था की गई है । सब्जियों की खेती के लिए भी अतिरिक्त सहायता दी गई है । राज्यो को राहत कार्यों में लगे कर्मचारियों को देने के लिए गेहूं की अतिरिक्त आपूर्ति के बारे मे भी बता दिया गया है । बच्चो और गर्भवती स्त्रियों तथा दूध पिलानेवाली माताओं का ध्यान रखने के लिए सूखे से प्रभावित सभी गैर-एकीकृत बाल विकास योजना वाले क्षेत्रों में पोषाहार कार्यक्रम के लिए भी केन्द्रीय

सहायता दी जा रही है । इसी प्रकार, बूढ़े, कमजोर और निराश्रित व्यक्तियों को मुफ्त सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है । पानी की कमी को दूर करने के लिए नलकूप खोदने की व्यवस्था करने और पानी की पूर्ति के लिए किए जाने वाले अन्य प्रबन्धों के लिए सहायता उपलब्ध कराई गई है । सूखे मे, बड़ी संख्या में पशु भी प्रभावित हुए हैं और सूखे के लिए जो सहायता दी गई है उसमे चारे और इसके रखरखाव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी शामिल है ।

सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए, रबी के उत्पादन में वृद्धि करने, पीने के पानी की अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और सूखा राहत सहायता के भाग के रूप में सूखे से निपटने के उपयुक्त उपाय करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

श्री मीर्जा इर्शादबेग : मान्यवर, सभापति जी, सदन के सर्वोच्च आसन पर आप के विराजमान होने के पश्चात् यह मेरा पहला मौका है कि मैं आपके सामने बोल रहा हूं । मैं आप को हृदय से बधाई देते हुए मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि देश को ईस्वी 2000 तक आत्मनिर्भर बनाने के लिए संवृद्धि की आवश्यक दशाएं उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में सातवीं पंचवर्षीय योजना में पांच परसेंट से अधिक विकास दर की आवश्यकता का निर्धारण किया गया था और कृषि के क्षेत्र में चार परसेंट की वार्षिक समग्र संवृद्धि तथा औद्योगिक क्षेत्र में 8 परसेंट की लक्षित संवृद्धि दरों की मात्रा को इस शतक के भयंकर सूखे ने विक्षिप्त किया है । किन्तु सरकार ने इससे निपटने के लिए रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन के अन्तर्गत सरचार्ज लगा करके आय उपार्जन का आयोजन किया है तो मैं मंत्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि इस सरचार्ज से कितनी राशि प्राप्त होगी और इस को किन-किन क्षेत्रों में कितनी मात्रा में उसका उपयोग किया जायेगा ? मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहूंगा कि इस सूखे के प्रभाव से बचाने के लिए जो अधिक राशि हम उपलब्ध कराना चाहते हैं उस को रखने के लिए जो कदम हम लाना चाहते है तो क्या जो प्लान हमने बनाया हैं उस प्लान मे सरकार कटौती करके ये संसाधन जुटाने की कोशिश कर रही है ?

श्री सुख राम : सभापति जी, जो अभी माननीय सदस्य ने इस बारे में जानना चाहा है कि कितने अधिक साधन उपलब्ध होंगे सरचार्ज के माध्यम से तो करीबन साढ़े पांच सौ करोड़ उपलब्ध होने की आशा है । जो दूसरे है जैसे कि वित्त मंत्रालय है उसके बारे मे आप को वहीं से जानकारी मिल सकती है कि यह राशि कहा से आयेगी मैं आप को इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि जो अधिक धनराशि राहत कामों के लिए राज्यों को हम देंगे वह धनराशि जो एडीशनल रिसोर्सेज है उससे हम पैदा करके दे रहे हैं और कोई भी जो योजना है उसमें से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी ।

अब यह प्रश्न है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितनी उपलब्धि होगी, कितना ग्रोथ होगा यह अभी तो नहीं कहा जा सकता । मगर मैं यह कह सकता हूं कि उसमें थोड़ा असर तो जरूर होगा । हमारा जो इकोनोमिक सेक्टर है वह थोड़ा फर्क के साथ जरूर आगे बढ़ेगा ।

श्री मीर्जा इर्शादबेग : मान्यवर, प्लान मे, योजना में कटौती किये बगैर राज्यों को, सूखे से लड़ने के लिए जो अधिक आवश्यकताएं हैं उससे संतुष्ट करना मैं समझता हूं यह सक्षम एवं कुशल एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रमाण है और इसके लिए प्रधान मंत्री जी तथा सरकार अभिनन्दन के पात्र है ।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सरचार्ज से जो वित्तीय संसाधन जुटाने के अतिरिक्त सरकार ने विश्व बैंक से सहायता मांगी तो यह राशि किस मात्रा में है और कब प्राप्त होगी और उस को किस क्षेत्र में खर्च करने की योजना है तथा योजना लक्ष्यांकों में इसकी पूर्ति किस प्रकार हो सकेगी ?

श्री सुख राम : यह वर्ल्ड बैंक या दूसरे विदेशो से हम को जो मदद मिलेगी वह कितनी राशि है वह वित्त मंत्रालय बता सकेगा । मगर मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जो भी इसके लिए धन उपार्जन किया जा रहा है एडीशनल रिसोंसिज जो इसके लिए मोबिलाइज किये जा रहे है उनको राज्यो मे वितरित किया जा रहा है एडवांस प्लान असिस्टेंस के जरिये और वह भिन्न भिन्न मदो पर खर्च होगा । मगर जहा तक भारत सरकार का ताल्लुक है हमने सभी राज्यों को एक बात कही है कि इस रुपये को इस तरह खर्च किया जाय जिससे एक तरफ तो लोगो को रोजगार मिले और दूसरी तरफ ऐसे कार्यक्रम बनाये जांय जिससे आइंदा आने वाला जो इस तरह का ड्राउट है, सूखे की स्थिति है उससे निपटा जा सके, जैसे कि भूमि संरक्षण कार्यक्रम है या सिंचाई के बड़े साधन हैं । इसके लिये भारत सरकार ने 118 करोड़ रुपये, सूखे में जो राहत दी है उसके अलावा राज्यों को उन योजनाओं को पूरा करने के लिये, जो उनकी मीडियम और मेजर इरीगेशन स्कीम्स है, जो आन-गोइंग है, चालू हैं, दी हैं और उनको कहा है कि वे इनको दो वर्षों के अन्दर पूरा करें ताकि उसके परिणामस्वरूप पैदावार ज्यादा बढ़ सके ।

SHRI VISHVJIT PRITHVIJIT SINGH: Mr. Chairman, Sir, it all very well to talk in terms of drought when it comes. But I would like to know from the hon. Minister what kind of apparatus he has set up for prediction of what is going to happen. We have had drought now. This is the third consecutive year. There are predictions that we are going to have drought next year and the year after that, of course on a lesser scale. Certain predictions are already there. I would like to know from the hon. Minister what is going to be done about the future? Are we making any provision for the future? Have we got any steps under way? Have we commissioned any steps? Have we got access to international reports? What is going to be our attitude towards the future?

SHRI SUKH RAM: Sir, I am not aware about any scientific method which can forecast with any great accuracy that drought is going to occur in future after so many years. What we have planned and what we are doing is that we have provided sufficient assistance to the State Governments, as I said earlier, for construction of medium and major irrigation schemes and minor irrigation schemes, so that agriculture becomes less dependent on the vagaries of nature.

SHRI K. MOHANAN: Sir, regarding the agriculture sector in his reply the Minister has mentioned about the loss in 'kharif' production and the steps taken to offset this loss in the 'rabi' production. But, Sir, in a State like Kerala, the problem is extremely different. Sixty per cent of our agricultural production is money crops. The after-effect of money crops due to continuous drought for the last seven years will be there for the next five or six years. So the long-term planning is quite different for cash crops and food crops. For example, Sir, for the replantation of a coconut tree it will take six years or seven years to get the yield. Like that, rubber, cardamom, etc. are earning a huge amount of foreign exchange also. It will affect our planning and the economic system as a whole. So my question is, will the Government give special attention to these aspects when you consider the longterm planning in the agricultural sector?

SHRI SUKH RAM: Sir, to meet this situation of drought is primarily the responsibility of State Governments. The Central Government advances plan assistance to the State Governments to tide over this problem so that their Plan is not affected. In case the hon Member wants that for Kerala some special plan should be prepared to protect the cash crops, it is for

the State Government to prepare such a plan. When they come to the Planning Commission for necessary assistance, that can be considered according to the formula which is applicable.

SHRI K. MOHANAN: The Central Government has granted 29 crores of rupees which is too meagre a sum.

SHRI P. SHIV SHANKER: I may add to what the hon. Minister has said. With reference to the money crops in Kerala which are export oriented, you are aware that there are Export Promotion Groups under the Commerce Ministry. Apart from that, there are also groups which take particular care of plantations and the growth of these crops. So far as the Planning Commission is concerned, they advise those plantation groups to properly prepare the schemes for plantations and their growth so that a long-term perspective could be taken care of in conjunction with the Commerce Ministry groups.

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, the statement made by the Government is simplified and over-optimistic. Sir, if you go through the views of various economic experts who have expressed their opinions, you will find that because of the fall in production in the Kharif crop, the agricultural income will go down to the extent of 10 to 15 per cent. Your figures also justify that. This will reduce the agricultural income by 14000 crores of rupees in the rural areas. If a reduction of 14000 crores of rupees, due to the fall in agricultural production during the Kharif season takes place, the purchasing power of the rural people will further go down by 9,000 to 10,000 crores of rupees. I would like to know from the Minister of Planning whether this will not change the entire profile of the next Plan. Recession has already started in the consumer industries throughout the country. I want to know whether this pumping of another 700 crores of rupees from here and there will solve the problem. I want to say that if you want to keep the Plan intact, major steps have to be taken to reduce the trade gap, to increase supplies to the rural population, to increase their purchasing power and to see that the industries are sustained. You have to see that the employment opportunities are not reduced on account of this drought. What steps does the Government propose to take in this connection?

SHRI SUKH RAM: Sir, there is no doubt that there will be a shortfall in the Kharif crop. We expect that it will be offset to a maximum extent in the rabi crop. That strategy has been prepared by the Agriculture Ministry in consultation with the State Governments. We are sure that there will be an increase in the rabi crop. The hon. Member has expressed the doubt that there will be decrease in he income of the rural people. He has quoted certain figures. I am not aware of those figures.

SHRI A. G. KULKARNI: These are Parliamentary Research Bureau's figures.

SHRI SUKH RAM: For instance, Sir, the hon. Member has mentioned about the performance of the industry. Industrial sector has been doing very well for the last three years. The growth rate ranges from 8.6 per cent in 1984-85 to 8.9 per cent in 1986-87. In spite of the fact that the agricultural growth in 1984-85 was negative and 1.4 per cent in 1985-86 and zero per cent in 1986-87, even then there was an industrial growth of 8.9 per cent which we never achieved...

SHRI A. G. KULKARNI: In what sector?

SHRI SUKH RAM: In the industrial sector.

SHRI A. G. KULKARNI: You have to go to the micro-analysis.

SHRI SUKH RAM: I am coming to that. Sir, the industries which showed better performance are given more weightage. Those industries are chemicals, chemical products, basic metal and allied industries, metal products, machine tools and parts, electrical machinery, transport equipment and miscellaneous industries. They constitute 44 per cent of the total industrial output. And the industries which are directly affected are: food processing, food products, beverages, tobacco, etc. And their contribution is 7 per cent. Then about fertilizers, though the consumption will be falling down in the kharif because of this drought, but we are very sure that this consumption will increase in the rabi. So, on this broad assessment, we can come to this conclusion that our planning performance or the performance by the various sectors will be not as bad as the hon. Member has expressed his apprehension. It may be slightly low but not to the extent which he says that it will affect the entire economy.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : देश आज सिंचाई के बदले मानसून पर निर्भर है और सिंचाई से केवल 22 प्रतिशत सिंचित है। योजना में इसकी 22 प्रतिशत से 32-42 प्रतिशत करने की कोई योजना है सूखे के लिए एक तो यह। दूसरा सूखे के बाद बाढ से हमारे देश को उतना ही नुक्सान होता है। बाढ नियंत्रण की योजना खास कर गैंजेटिक लेन में कुछ नहीं है। इन दोनों को व्यवस्थित करने के लिए पंचवर्षीय योजना में खासकर इसके लिए कोई योजना बनाने का विचार है या बनायी है ? राहत कार्य के बारे में आपने कहा है। मैं चाहता हूं कि राहत का कार्य जो स्टेट करें वे सचमुच में विकास के काम को आगे बढ़ाने के लिए हो... (व्यवधान) इसलिए क्या कोई निश्चित कार्यक्रम बनाकर आप स्टेट्स को दे सकते है कि स्टेट्स उस दायरे में काम करें और राहत का काम टेम्पोरेरी फेज वाला नहीं हो, स्थायी फेज वाला हो।

श्री सुखराम : जैसा मैंने पहले कहा कि भारत सरकार की जो प्राथमिकता है वह सिंचाई के लिए है और इसमें अभी राहत मे जो प्लान असिस्टेंस दी वह और 236 करोड़ रुपया हमने महज सिंचाई की योजनाओं के लिए भिन्न भिन्न सरकारों को, जो ड्राउट एफेक्टेड है, दिया है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि उसको ऐसे कार्यक्रम मे लगाया जाये जिससे कि आगे आने वाले समय मे इस विपत्ति से बच सकें तो हमने सभी राज्यों को इसके बारे मे कहा है. . (व्यवधान)

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : वह तो आपने पहले भी कहा। ऐसे कार्यक्रम बनाकर दिखाये हैं कि इस तरह के काम को आगे बढ़ाये। एडवाइज सीधे देने से कार्यक्रम बनता नहीं है। कोई निश्चित कार्यक्रम बनाकर दीजिए।

श्री सुखराम : ऐसे कार्यक्रम प्रांतीय सरकारें बनाती हैं और जो बड़े कार्यक्रम है वे हमारे पास विचाराधीन है। उनके बारे मे विचार करेंगे कि और क्या उसमे इम्प्रूवमेंट हो सकता है ताकि इस प्रकार की विपत्ति से बच सकें।

SHRI JAGESH DESAI: Mr. Chairman, Sir, the drought conditions in our country have very seriously affected two crops in our country, that is groundnut and pulses. And these two crops, as you know, Mr. Chairman, are grown by small and marginal farmers only. Stagnation in the production of these two crops in the last ten to fifteen years, with only a very marginal increase in the case of oilseeds and no increase in the production of pulses, has resulted in the prices of oils and prices of arhar and other pulses going up to Rs. 15 per kg. I would like to know from the Government whether they are thinking to apply the insurance scheme for these two crops throughout the country, instead of only to a few districts and whether they will not charge any premium on this insurance. Secondly, whether the Government is thinking to give some kind of a subsidy for the growth of

these two crops to marginal farmers so that they can be given incentive and these two crops can be produced to some extent and the problem can be solved.

MR. CHAIRMAN: Shri Nirmal Chatterjee.

AN HON. MEMBER: The Minister has not replied yet.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: The Minister can reply to his question and my question together.

SHRI SUKH RAM: Sir, this question can be better replied by the Agriculture Ministry. But what I am stating for the information of the Hon. Member is that there is already a scheme applicable to certain parts of the country where incentives are given for growing pulses and edible oilseeds There is no doubt that there is some shortage of pulses and edible oils and the Government of India have taken appropriate steps to import these articles so that there is no shortage in the country on account of these commodities.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE : Sir, I agree more with the Minister's statement than with Mr. Kulkarni.

MR. CHAIRMAN: Please come to the question.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE : This is some padding, which the Prime Minister also likes. According to the statement, the assessment of the Planning Commission is that despite the severity of the drought, the economy as a whole will record a positive growth and the targets will be fulfilled. This, I agree, because the targets of growth in the economy do not depend on the production inside the country. It depends on whether the battle in Sri Lanka will continue and our defence expenditure will go up.

MR. CHAIRMAN: Please come to the point.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE : Yes, Sir, I am coming. It depends on whether despite the understanding between Vice-President, Bush, and our Prime Minister, the CIA activities inside the country will be intensified, leading to destabilisation and therefore more police and greater expenditure on police will take place. It is in this area that we are comparable with the advanced countries of the world. It is the service sector which permits you to fulfil the target, not the physical goods production sector. Therefore my question is very simple. The question is along with the fulfilment of targets, because of the drought, how many more people would you succeed in pushing below the poverty line? Is there any estimate?

MR CHAIRMAN: He wants to know what is the influence of the CIA on planning.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: He is taking a negative attitude.

SHRI SUKH RAM: Sir, as far as poverty line is concerned, the situation will be known after some time. But his supplementary has no relevance to the question. We have already made in emphatically clear that the Central plan will be 100 per cent protected and will try to achieve the targets. Only there may be some shortfall in the rabi crops and there may be some problems for which he Central Government has provided the necessary assistance to all the State Governments to meet the situation.

Talks held by the P.M. with the U.S. President

*84. SHRI J P. GOYAL: †
SHRI RAM AWADHESH SINGH:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) What were the issues discussed

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri J. P. Goyal.